दिसम्बर, 1964 को समाप्त होने वाले वर्ष की जानकारी का अभी संकलन नहीं हुआ है ।

†[THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO-OPERATION (SHRI B. S. MURTHY): There were 7 General Insurance Co-operatives with a total paid-up share capital of Rs. 27.17 Lakhs and Insurance Fund of Rs. 49.07 lakhs as on 31st December, 1963. Information for the year ending 31st December, 1964, is not yet compiled.]

सहकारिता सम्बन्धी विधान

510. **श्री भगवत नारायण भार्गव :** क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय विकास परिषद् के नीति विषयक निर्णय के अनुसार उत्तर प्रदेश, केरल और संघ-राज्य क्षेत्रों में सहकारिता सम्बन्धी विधान के कब तक अधिनियमित किये जाने की संभावना है ?

†[CO-OPERATIVE LEGISLATION

510. SHRI B. N. BHARGAVA: Will the Minister of COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO-OPERATION be pleased to state as to when co-operative legislation is likely to be enacted in Uttar Pradesh, Kerala and the Union Territories in pursuance of the policy decision of the National Development Council?]

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बी० एस० मूर्ति) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

उत्तर प्रदेश:—सहकारी समिति विधेयक राज्य विधान सभा में पेश किया गया था और वह संयुक्त प्रवर समिति को सौपा गया है ।

केरल:—केरल सहकारी समिति विधेयक राज्य विधान सभा में पेश किया गया था । राष्ट्रपति का शासन लागू किये जाने के परिणामस्वरूप विधान सभा के भंग होने से वह व्यवगत हो गया ।

पांडिचेरी :—पांडिचेरी प्रशासन ने हाल ही में एक नया विधान बनाया है ।

हिमाचल प्रदेश:—हिमाचल प्रदेश सहकारी समिति विधेयक तैयार है जो हिमाचल प्रदेश विधान सभा के अगले अधिवेशन में पेश किया जाएगा ।

दिल्ली:—यह निर्णय किया गया है कि दिल्ली में लागू बम्बई सहकारी समिति अधिनियम, 1925 को हटाने और पंजाब सहकारी समिति अधिनियम 1961 को कुछ संशोधनों के साथ दिल्ली में लागू करने के लिए वैधानिक कार्यवाही की जाए । आशा है कि संसद् में एक विधेयक पेश किया जाएगा ।

अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह :—प्रशासन, विनियम का मसौदा तैयार करने के बारे में विचार कर रहा है, जो राष्ट्रपति द्वारा इस समय लागू सहकारी समिति अधिनियम, 1912 को बदलने के लिए प्रख्यापित किया जाएगा ।

त्रिपुरा :—इस समय बम्बई सहकारी अधिनियम, 1925 लागू है । वर्तमान आवश्यकताओं के अनरूप सांविधिक नियमों में अतिरिक्त उपबन्ध किये गये हैं ।

गोवा, दमण तथा दीव :—इस क्षेत्र में महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम, 1960 लागू किया गया है ।

† [ ] English translation.

दादरा तथा नगर हवेली :—इस क्षेत्र में गुजरात सहकारी समिति अधिनियम, 1961 लागू किया गया है ।

लकादिवी:—लकादिवी, मिनीकोय तथा अमिनदिवी द्वीप समूह सहकारी समिति विनियम, 1960 दिसम्बर, 1961 से लागू किया गया है ।

मनीपुर :—मनीपुर में असम सहकारी समिति अधिनियम, 1949 लागू है । नया सहकारी कानून बनाने का प्रश्न मनीपुर प्रशासन के विचाराधीन है ।

नेफा :—इस संघ क्षेत्र में सहकारी समिति अधिनियम, 1912 लागू है । नेफा प्रशासन से अनुरोध किया गया है कि वह नया विधान बनाने के बारे में विचार करे ।

†[THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO-OPERATION (SHRI B. S. MURTHY): A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

Uttar Pradesh.—A Co-operative Societies Bill was introduced in the State Assembly and it has been referred to a Joint Select Committee.

Kerala.—The Kerala Co-operative Socities Bill, which had been introduced in the State Assembly, lapsed due to dissolution of the Assembly as a result of the promulgation of the President's Rule.

Pondicherry.—Pondicherry Administration has recently enacted a new legislation.

Himachal Pradesh.—The Himachal Pradesh Co-operative Societies Bill is ready for introduction in the next session of the Himachal Pradesh Assembly.

Delhi.—A decision has been taken to initiate legislative action to repeal the Bombay Co-operative Societies Act, 1925 in its application to Delhi and to extend the Punjab Co-operative Societies Act, 1961 with some modifications to Delhi. A Bill is expected to be introduced in the Parliament.

Andaman and Nicobar Islands.—The Administration is considering the preparation of draft regulation to be promulgated by the President in order to replace the Co-operative Societies Act of 1912, which is now in force.

Tripura.—The Bombay Co-operative Societies Act 1925 is now in force. Additional provisions have been made in the statutory rules to suit the present requirements.

Goa, Daman and Diu.—The Maharashtra Co-operative Societies Act, 1960 has been extended to this Territory.

Dadra and Nagar Haveli.—The Gujarat Co-operative Societies Act, 1961 has been extended to this Territory.

Laccadivi.—The Laccadivi, Minicoy and Amindivi Islands Co-operative Societies Regulation, 1960 has been brought into force since December, 1961.

Manipur.—The Assam Co-operative Societies Act, 1949 is in force in Manipur. The question of enacting a new co-operative law is under consideration of the Manipur Administration.

Nefa.—The Co-operative Societies Act of 1912 is in force in this Union Territory. The NEFA Administration has been requested to consider the enactment of new legislation.]

LOANS TO CO-OPERATIVE SOCIETIES

511. SHRI DEOKINANDAN NARAYAN: Will the Minister of COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO-OPERATION be pleased to state the amount of money so far given to each State

† [ ] English translation